



Neutral Citation No. - 2026:AHC-LKO:19504

प्रकाशनार्थ स्वीकृत

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

रिट - ए संख्या - 6977/ 2023

प्रशांत राव

.....याचिकाकर्ता

बनाम

भारत संघ, द्वारा सचिव, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली और 4 अन्यप्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, अविरल सिंह, विजय नंदन मणि त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : ए.एस.जी.आई., अनिल कुमार श्रीवास्तव, नीरज अवस्थी

न्यायालय संख्या - 18

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी, जिनकी सहायता संजीव कुमार मिश्रा ने की और प्रतिवादी-बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता अनिल कुमार श्रीवास्तव की दलीलें सुनी गईं; भारत संघ की ओर से कोई उपस्थित नहीं था।

2. इस रिट याचिका के ज़रिए, याचिकाकर्ता ने विपक्षी संख्या 4 द्वारा 17-07-2023 को पारित आदेश और मुख्यालय द्वारा 27-06-2023 को जारी आदेश/पत्र को चुनौती दी है।

3. याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अमरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने इस न्यायालय का ध्यान 27-06-2023 के उस आदेश/पत्र की ओर दिलाया, जो प्रतिवादी-बीमा कंपनी द्वारा दाखिल पूरक प्रति-शपथपत्र के पृष्ठ 7 पर लगा है। उन्होंने तर्क दिया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर विचार अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने के लिए लागू नियमावली के अनुसार, यदि जीवनसाथी काम कर रहा है और सहायक संवर्ग के शुरुआती स्तर पर मिलने वाले कुल वेतन (ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स) के बराबर या उससे ज़्यादा कमा रहा है, तो परिवार के किसी अन्य सदस्य का आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। हालांकि, इस मामले में जीवनसाथी न तो 'काम कर रहा है' और न ही 'कमा रहा है', क्योंकि आवेदक के पिता की मृत्यु के बाद उनकी माँ को पेंशन मिल रही है, जो वेतन के दायरे में नहीं आती है। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु नौकरी के दौरान 02-06-2020 को हुई थी और 15-06-2020 को याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी-बीमा कंपनी के क्षेत्रीय कार्यालय में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया था। कई अनुस्मारक भेजने के बाद 27.06.2023 को इसे खारिज कर दिया गया और इसकी जानकारी 17-07-2023 के पत्र के माध्यम से दी गई। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने का जो आधार 27-06-2023 के आदेश में बताया गया है—यानी याचिकाकर्ता की माँ को मिलने वाली पेंशन को परिवार के 'काम करने वाले और कमाने वाले सदस्य' के तौर पर माना जाना—वह आधारहीन है और कानून के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है।

4. उन्होंने तर्क दिया कि असल में पेंशन को एक समय-समय पर मिलने वाले भुगतान के तौर पर देखा जाता है, जो पिछली सेवाओं के आधार पर अधिकार, विशेषाधिकार या ज़रूरी शर्त के तौर पर दिया जाता है।

5. उन्होंने इस न्यायालय का ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा '**गोविंद प्रकाश वर्मा बनाम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया और अन्य**' (वाद संख्या (2005) 10 सर्वोच्च न्यायालय वाद 289) के वाद में तय किए गए कानून की ओर दिलाया।

6. ऊपर बताए गए निर्णय का हवाला देते हुए, उन्होंने कहा कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की योजना, मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों को सेवा से जुड़े उन फायदों के अलावा है जो कर्मचारी की मृत्यु पर मिलते हैं। उन्होंने तर्क दिया कि नियुक्ति से इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता कि परिवार को नियमों के तहत सेवा लाभ के रूप में कुछ रकम मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि मृतक की विधवा को पारिवारिक पेंशन के तौर पर या नियमों के तहत टर्मिनल बेनिफिट्स (सेवा समाप्ति पर मिलने वाले लाभ) के तौर पर दी जाने वाली रकम को परिवार की कमाई नहीं माना जाना चाहिए।

7. अपनी दलीलें रखते हुए, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारियों पर लागू 'अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति' की योजना के उपबंध 10.1 पर ध्यान दिए बिना ही संबंधित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिकारियों ने 27-06-2023 का आदेश जारी किया; इसलिए, अधिकारियों ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए तय प्रावधान को गलत समझा है। उन्होंने कहा कि जिन आदेशों को चुनौती दी गई है, वे न केवल गलत हैं, बल्कि कानून के स्थापित सिद्धांतों के भी खिलाफ हैं और इसलिए, उन्हें बरकरार नहीं रखा जा सकता।

8. अपनी दलीलें समाप्त करते हुए, उन्होंने कहा कि जिन आदेशों को चुनौती दी गई है, उनसे साफ पता चलता है कि उनमें कोई कारण नहीं बताया गया है और आवेदक की नियुक्ति की मांग को बहुत सतही तौर पर खारिज कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि कानून का स्थापित नियम है कि हर आदेश अपने आप में सही और ठोस होना चाहिए, जो इस मामले में नहीं है; इसलिए, उनका कहना है कि यह आदेश टिकने लायक नहीं है।

9. दूसरी ओर, प्रतिवादी-बीमा कंपनी की ओर से प्रस्तुत हुए विद्वान अधिवक्ता श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव ने ऊपर बताई गई बातों का विरोध किया और इस न्यायालय का ध्यान प्रति शपथपत्र के पैराग्राफ संख्या 7 और 9 में कही गई बातों की ओर दिलाया। उन्होंने तर्क दिया कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की योजना के तहत नियुक्ति, सरकारी नौकरी में 'बैंक डोर एंट्री' (अवैध या अनौपचारिक तरीके से प्रवेश) का ज़रिया नहीं हो सकती और यह कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। उन्होंने आगे कहा कि सरकारी सेवा में नियुक्तियाँ पूरी तरह से खुली भर्ती प्रक्रिया के आधार पर की जाती हैं, जबकि "योजना" के तहत दया के आधार पर नियुक्ति उन कर्मचारियों के आश्रितों के लिए होती है जिनका परिवार गरीबी और आजीविका के किसी साधन के बिना रह जाता है; और जहाँ तक इस मामले का सवाल है, संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्णय लेते समय पेश किए गए दस्तावेजों से स्पष्ट है कि ऐसी कोई स्थिति मौजूद नहीं है।

10. अपनी बातों के समर्थन में, उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **(2007) 9 सर्वोच्च न्यायालय वाद 571, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया और अन्य बनाम जसपाल कौर** वाद के निर्णय का हवाला दिया है और उस निर्णय के प्रस्तर संख्या 20 से 25 का ज़िक्र किया है, जो नीचे दिए गए हैं:-

"20. मृत कर्मचारी पर निर्भर लोगों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने के बारे में कानून इस न्यायालय ने 'उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य' [(1994) 4 एससीसी 138 : 1994 एससीसी (एलएंडएस) 930 : (1994) 27 एटीसी 537]

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मामले में तय किया था, जिसमें न्यायालय ने कहा था कि: (एससीसी पृष्ठ 139-40,

पैरा 2)

सरकारी सेवाओं में नियुक्तियाँ पूरी तरह से आवेदन मँगाने और योग्यता के आधार पर की जाती हैं। हालाँकि, उन कर्मचारियों के आश्रितों के मामले में अपवाद किए जाते हैं जिनकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो जाती है और जिनका परिवार गरीबी और आजीविका के किसी साधन के बिना रह जाता है।

21. इस न्यायालय ने जी. एम. (डी.एन्ड पी.बी.) बनाम कुंती तिवारी [(2004) 7 एससीसी 271: 2004 एससीसी (एलएंडएस) 943] मामले में आगे यह भी कहा है कि: (एससीसी पृष्ठ 274, प्रस्तर 9)

"उनकी आय का विवरण उनके आवेदन में दिया गया है और उसके आधार पर निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि प्रतिवादी बहुत तंगहाली में जी रहे थे। खंडपीठ ने गरीबी के इस पैमाने को बदलकर 'बहुत अमीर न होने' जैसा बना दिया, जो कि एक गलती थी।"

22. इस न्यायालय ने 2005 में 'स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम विकास दुबे' [सी ए संख्या 7003/2005, दिनांक 21-11-2005, रिपोर्ट: (2007) 9 एससीसी 579] मामले में फिर से यही बात कही थी और 'कुंती तिवारी' मामले [(2004) 7 एससीसी 271 : 2004 एससीसी (एलएंडएस) 943] के फैसले का पालन किया था।

23. इसलिए, अनुकम्पा के आधार पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करते समय एक मुख्य पैमाना यह होना चाहिए कि मृतक व्यक्ति के परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है। जब तक परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब या तंगहाली वाली न हो, तब तक ऐसी नियुक्तियाँ नहीं की जा सकतीं। इस मामले में, प्रतिवादी के परिवार की आर्थिक स्थिति तंगहाली वाली नहीं है; अपीलकर्ताओं ने पहले ही टर्मिनल बेनिफिट्स के तौर पर 4,57,607 रुपये का भुगतान कर दिया है (देनदारियों के लिए 19,183 रुपये काटने के बाद); साथ ही, 'कर्मचारी पारस्परिक कल्याण योजना' के तहत परिवार को हर महीने 2055 रुपये पेंशन और मासिक आय के तौर पर मिल रहे थे। इसके अलावा, परिवार की कुल मासिक आय 5855 रुपये है (2055 रुपये मासिक पेंशन + 4,57,607 रुपये के निवेश पर काल्पनिक ब्याज के तौर पर 3800 रुपये प्रति माह)। तथ्यों की जांच करने वाले सक्षम अधिकारी ने ऊपर दी गई आर्थिक जानकारी के आधार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पर यह निष्कर्ष निकाला कि परिवार की आर्थिक स्थिति तंगहाली वाली नहीं है और परिवार अपना गुजारा करने के लिए पर्याप्त आय कमा रहा है। इसलिए, प्रतिवादी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं दी गई। हालांकि, इस मामले के तथ्यों को देखते हुए हमें बैंक प्राधिकारी के इस आदेश में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं लगती।

24. बैंक के सक्षम प्राधिकारी को योजना में तय किए गए नियमों के अनुसार प्रतिवादी के मामले पर विचार करना था। इसी के अनुसार, प्रतिवादी की आर्थिक स्थिति पर फैसला करते समय सक्षम अधिकारी ने इन बातों पर ध्यान दिया:

(ए) पारिवारिक पेंशन

(बी) ग्रेच्युटी

(सी) प्रोविडेंट फंड में कर्मचारी/नियोक्ता का योगदान

(डी) बैंक या उसके कल्याण कोष द्वारा दिया गया कोई भी मुआवजा

(ई) मृतक कर्मचारी की एलआईसी पॉलिसी और अन्य निवेशों से मिली रकम

(एफ) परिवार की अन्य स्रोतों से आय

(जी) परिवार के अन्य सदस्यों का रोजगार

(एच) परिवार का आकार और देनदारियां (अगर कोई हों) आदि। इन विवरणों के आधार पर, अनुकम्पा के आधार पर प्रतिवादी की नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया गया।

25. साथ ही, हमारी राय है कि नियमों या विनियमों के तहत विशेष रूप से गठित अधिकारी (जैसे इस मामले में सक्षम अधिकारी) मामले के तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए बेहतर स्थिति में होते हैं और सभी तथ्यों को समझने के बाद उनके निष्पक्ष निष्कर्ष में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। इस मामले की सुनवाई करने वाली उच्च न्यायालय की दोनों पीठों ने प्रतिवादी के दावे पर विचार करने और उसे स्वीकार करने में गलती की है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया बनाम एम.टी. लथीश [(2006) 7 एससीसी 350 : 2006 एससीसी (एलएंडएस) 1646] मामले में इस कोर्ट के हालिया फैसले में भी यही राय व्यक्त की गई थी, जिसमें न्यायालय ने कहा था: (एससीसी पी. 365, पैरा 37)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"नियुक्ति का आदेश देकर, विद्वान एकल न्यायमूर्ति और खंडपीठ ने नियुक्ति और चयन करने वाले अधिकारियों के विवेक पर रोक लगा दी है। बैंक ने इस तरह की नियुक्ति के लिए बनाई गई कानूनी योजना के अनुसार प्रतिवादी के आवेदन पर विचार किया था।"

11. ऊपर बताई गई बातों का जिक्र करते हुए, उनका कहना है कि यह मामला पूरी तरह से ऊपर बताए गए निर्णय के दायरे में आता है और इसलिए, इसमें किसी हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है।

12. दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद, यह पता चलता है कि याचिकाकर्ता के पिता की नौकरी के दौरान 02-06-2020 को मृत्यु हो गई थी। इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अनुकम्पा के आधार पर नौकरी के लिए अर्जी दी थी, लेकिन उसे बिना किसी ठोस आधार के खारिज कर दिया गया।

13. असल बात यह है कि याचिकाकर्ता की माँ नौकरी करती थीं और अब वे सेवानिवृत्त हो चुकी हैं और उन्हें पेंशन मिल रही है। जब 02-06-2020 को याचिकाकर्ता के पिता की मौत हुई, तो वे अपने पीछे कानूनी वारिस छोड़ गए - श्रीमती प्रेम कुमारी राव (पत्नी), सिद्धांत राव (बेटा) और प्रशांत राव (बेटा)।

14. याचिकाकर्ता ने भारत सरकार द्वारा बनाई गई 'अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति योजना, 2014' (जिसे आगे 'योजना, 2014' कहा जाएगा) के अंतर्गत नौकरी का दावा किया। 'योजना, 2014' को संबंधित विभाग ने अपनाया है और यह सभी कर्मचारियों पर लागू होती है। 'योजना, 2014' में बाद में 03-04-2018 को संशोधन किया गया (जो 23-03-2018 से लागू हुआ), जिसे संबंधित विभाग ने 07-06-2018 के सर्कुलर के ज़रिए अपनाया। 'योजना, 2014' के संबंधित प्रावधान, यानी उपबंध 10.1 और 10.2, जो नियुक्ति की शर्तों के बारे में बताते हैं, नीचे दिए गए हैं:-

10.1

अगर जीवनसाथी नौकरी कर रहा है और सहायक संवर्ग में शुरुआती स्तर पर मिलने वाले कुल वेतन (ग्रॉस एमोल्यूमेंट्स) के बराबर या उससे ज्यादा कमा रहा है, तो परिवार के किसी दूसरे सदस्य की अर्जी खारिज कर दी जाएगी। हालाँकि, अगर जीवनसाथी अपनी मौजूदा नौकरी के बजाय इस योजना के तहत नियुक्ति के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उस पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते वह

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस्तीफा दे दे और कंपनी में शामिल होने से पहले अपने मौजूदा नियोक्ता से कार्यमुक्ति आदेश जमा करे।

10.2

अगर जीवनसाथी नौकरी करता है और उसकी कमाई सहायक संवर्ग में शुरुआती स्तर पर मिलने वाली कुल सैलरी से कम है, तो परिवार के किसी दूसरे आश्रित सदस्य के आवेदन पर विचार किया जा सकता है। ऐसा तब भी किया जा सकता है जब परिवार में कोई कमाने वाला सदस्य पहले से मौजूद हो, बशर्ते जीवनसाथी से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (एनओसी) मिल जाए।"

15. अस्वीकृति का आदेश साफ तौर पर बताता है कि यह आदेश प्रतिवादी-बीमा कंपनी के कर्मचारियों पर लागू योजना 2014' के उपबंध 10.01 के प्रावधानों को ध्यान में रखकर पारित किया गया है, जिसमें 23-03-2018 से संशोधन किया गया था। इस निर्णय में "काम करने और कमाई करने" शब्दों पर ज़ोर दिया गया है और याचिकाकर्ता की माँ को पेंशन से जुड़े लाभ के तौर पर मिली राशि को 'कमाई' के दायरे में माना गया है, जबकि सच्चाई यह है कि याचिकाकर्ता की माँ, जो पेंशन ले रही हैं, कोई कामकाजी कर्मचारी नहीं हैं, क्योंकि पेंशन कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद दी जाती है और यह पिछली सेवाओं के लिए भुगतान होती है।

16. पी. रामनाथ अय्यर की "मेजर लॉ लेक्सिकॉन" में 'पेंशन' और 'कमाई' शब्दों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:-

"पेंशन: पेंशन जनता के लिए पहले की गई सेवाओं के बदले मिलने वाला एक इनाम या भुगतान है। इसका मुख्य मकसद पेंशन पाने वाले व्यक्ति की रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करना है।

कमाई: जो कमाया गया हो; इनाम; मेहनत से हासिल की गई चीज़; निजी सेवाओं के बदले मिलने वाला इनाम, चाहे वह पैसे के रूप में हो या किसी और चीज़ के रूप में; की गई सेवाओं की कीमत; बिना किसी पूंजी की मदद के सेवा या मेहनत से हुई कमाई। कभी-कभी इस शब्द का मतलब सिर्फ मज़दूरी से कहीं ज़्यादा होता है।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



17. 'कमाई' शब्द का मतलब है वर्तमान में कुछ हासिल करना; यानी अगर सेवाएँ अभी दी जा रही हैं, तो उसका कुछ प्रतिफल भी अभी ही मिलता है। पेंशन कोई इनाम या खेरात नहीं, बल्कि एक अधिकार है; इसलिए, जो सेवाएँ पहले ही दी जा चुकी हैं, उन्हें 'कमाई' नहीं कहा जा सकता, और इसलिए पेंशन पाने वाले व्यक्ति को 'कमाई करने वाला व्यक्ति' नहीं माना जा सकता।

18. इस मामले में, मृतक कर्मचारी के जीवनसाथी यानी याचिकाकर्ता की माँ 'पेंशन' पा रही हैं; यह पेंशन उन्हें उनके मौजूदा काम-काज की स्थिति के लिए नहीं, बल्कि उनकी पिछली सेवाओं के लिए मिल रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शौकत हुसैन बेग मिर्ज़ा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य (एआईआर 1959 एएलएल 769) के मामले में 'पेंशन' के बारे में जो कहा है, वह इस प्रकार है:-

"मुझे लगता है कि पेंशन के लिए दो ज़रूरी बातें होनी चाहिए:

(1) यह समय-समय पर किया जाने वाला भुगतान होना चाहिए, और

(2) यह किसी अधिकार, विशेषाधिकार, ज़रूरी शर्त या पद के बदले में नहीं, बल्कि राजनीतिक कारणों, पिछली सेवाओं, मौजूदा शारीरिक अक्षमता या सहानुभूति के तौर पर दिया जाने वाला अनुदान होना चाहिए।

इसे पिछली सेवाओं के लिए समय-समय पर किया जाने वाला नकद भुगतान माना गया है (म्युनिसिपल काउंसिल, सलेम बनाम गुरुराज राव देखें)। यह जनता या राज्य के लिए की गई पिछली सेवाओं के बदले दिया जाने वाला इनाम है। इसका मुख्य मकसद पेंशन पाने वाले की रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करना है। यह सरकार द्वारा पेंशन पाने वाले या उसके किसी रिश्तेदार या पूर्वज की बेहतरीन पिछली सेवाओं को मान्यता देते हुए या उनके बदले में दिया जाने वाला इनाम या ग्रेच्युटी है।"

19. असल बात यह है कि मृतक कर्मचारी के जीवनसाथी, यानी याचिकाकर्ता की माँ, कोई कार्यरत कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। इसलिए, सिर्फ़ इसलिए कि किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी को हर महीने 'पेंशन' मिलती है, उन्हें 'कार्यरत कर्मचारी' नहीं माना जाएगा।

20. इसके अलावा, योजना 2014' के तहत अनुकम्पा के आधार पर नौकरी के प्रावधान में इस्तेमाल किए गए शब्द 'कमाई' में सेवानिवृत्त कर्मचारी को मिलने वाली 'पेंशन' शामिल नहीं है। 'कमाई' शब्द का अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मतलब है 'बिना किसी पूंजी की मदद के सेवा या मेहनत से होने वाली कमाई', जैसा कि पी. रामनाथ अय्यर की 'मेजर लॉ लेक्सिकॉन' में बताया गया है।

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गोविंद प्रकाश वर्मा बनाम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया और अन्य (वाद संख्या 2005 10 एससीसी 289) के मामले में भी यह कहा है:-

"6. हमारी राय में, विभाग के अधिकारियों और एकल न्यायमूर्ति के लिए उस रकम पर विचार करना पूरी तरह से अप्रासंगिक था जो मृतक की विधवा को पारिवारिक पेंशन के तौर पर दी जा रही थी (यह रकम, अपील करने वाले के अनुसार, अब आधी कर दी गई है) और नियमों के तहत टर्मिनल बेनिफिट्स के तौर पर दी गई अन्य रकमों पर भी। अनुकम्पा के आधार पर नौकरी की योजना, मृतक कर्मचारी के कानूनी उत्तराधिकारियों को मिलने वाले सेवा लाभ (जो कर्मचारी की मृत्यु पर मिलते हैं) के अलावा होती है। इसलिए, इस आधार पर अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि परिवार के किसी सदस्य को नियमों के तहत मिलने वाली रकम मिली है। जहाँ तक बड़े भाई के फायदेमंद रोज़गार (गेनफुल एम्प्लॉयमेंट) का सवाल है, हमें पता चला है कि यह बताया गया था कि वह खेती में लगा हुआ है। हमें नहीं लगता कि अगर परिवार के पास ज़मीन का कोई टुकड़ा है और परिवार का कोई सदस्य उस खेत में खेती करता है, तो इसे फायदेमंद रोज़गार माना जा सकता है। इस बयान का खंडन तब माना जाता है जब यह कहा जाता है कि बड़े भाई ने कहा था कि वह पेंटर के तौर पर काम करता है। यह ज़रूरी नहीं कि कोई विरोधाभास हो, और इससे यह नतीजा तो बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता कि वह कहीं पेंटर के तौर पर फायदेमंद रोज़गार में लगा हुआ था। हो सकता है कि वह अपने खेत में काम कर रहा हो और कभी-कभार पेंटर का काम भी मिल जाता हो। जाँच रिपोर्ट में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि वह नियमित पेंटर के तौर पर कहाँ काम करता था। जिन अन्य पहलुओं पर अधिकारी को जाँच करनी थी, उन्हें जानबूझकर छोड़ दिया गया और अधिकारी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में उनका कोई ज़िक्र नहीं है। इन हालात में, हमारी राय में, उच्च न्यायालय के आदेश टिकने लायक नहीं हैं। प्रतिवादियों ने अपील करने वाले को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने से गलत तरीके से इनकार किया है। बड़े भाई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के फायदेमंद रोजगार होने के नतीजे के आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती थी।

विधवा को मिले टर्मिनल बेनिफिट्स और पारिवारिक पेंशन को ध्यान में नहीं रखा

जा सकता था।"

22. यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि 'अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति' की योजना, मृतक कर्मचारी के उत्तराधिकारियों को मिलने वाले सेवा-लाभों के अलावा, कानूनी प्रतिनिधि को मिलने वाला एक लाभ है; इसलिए, इस आधार पर इसे मना नहीं किया जा सकता कि परिवार के सदस्य को नौकरी समाप्त होने के बाद मिलने वाले लाभ मिल रहे हैं।

23. ऊपर बताई गई बातों और चर्चाओं को देखते हुए, मेरी यह राय है कि 2014 की योजना के उपबंध 10.1 के प्रावधानों का हवाला देते हुए, मृतक के जीवनसाथी, यानी याचिकाकर्ता की माँ की स्थिति को गलत तरीके से परिवार के 'काम करने वाले और कमाने वाले' सदस्य के रूप में माना गया है।

24. नतीजतन, यह न्यायालय रिट याचिका में दम पाती है; इसलिए, 27.06.2023 और 17.07.2023 के विवादित आदेशों/पत्रों को रद्द किया जाता है।

25. प्रतिवादी-अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता के 15-06-2020 के आवेदन पर, इस आदेश की प्रमाणित प्रति उनके सामने पेश किए जाने की तारीख से आठ सप्ताह के भीतर, मौजूदा कानूनों और ऊपर की गई टिप्पणियों का पालन करते हुए नया निर्णय लें।

26. रिट याचिका तदनुसार स्वीकार की जाती है।

मार्च 17, 2026

एकेएस

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।